राष्ट्रीय संस्करण

क्रिकेट मैच के आयोजन से बड़ा मुद्दा है प्रदूषण

>>2

वर्ष 3 अंक 142

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 31 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

एक देश, एक विधान और एक निशान का सपना साकार

ऐतिहासिक क्षण ▶ देश के नक्शे पर दिखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश, जीसी मुर्मू श्रीनगर तो आरके माथुर लद्दाख में लेंगे उपराज्यपाल की शपथ

जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और कानून पूरी तरह निष्प्रभावी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

31 अक्टूबर गुरुवार की सुबह उम्मीदों का नया सूरज लेकर आएगी और 70 वर्षों की लंबी जद्दोजहद के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक देश, एक विधान और एक निशान का सपना साकार होगा। जम्मू-कश्मीर राज्य अतीत का हिस्सा बन जाएगा और दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के नक्शे पर उभर आएंगे। दोनों ही जगह अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्था होगी, जिसकी कमान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल संभालेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर श्रीनगर स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे, जबकि राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में लेह में शपथ लेंगे। लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित

जीसी मुर्मू

आरके माथुर (फाइल)

राज्य होगा, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल सुबह लेह में आरके माथुर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और उसके बाद वह विशेष विमान में श्रीनगर पहुंचेगी और यहां जीसी मुर्मू को शपथ दिलाएंगी। जीसी मुर्मू बुधवार को श्रीनगर पहुंच गए।

समारोह की पूरी तैयारी : पूर्व रक्षा सचिव माथुर सुबह 7.45 बजे लेह स्थित सिंधु संस्कृति केंद्र में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह सुबह 7.30 बजे शुरू होगा। इसकी तैयारियों की देखरेख कर रहे कमिश्नर सचिव लद्दाख रिगजिन सम्पेल ने बताया कि सभी प्रबंध हो गए हैं। वहीं श्रीनगर में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जीसी मुर्मू को सुबह पौने बारह बजे शपथ दिलाने का कार्यक्रम है। मुख्य न्यायाशीध गीता मित्तल को लेह से आना है। अगर उनके पहुंचने में देरी होती है तो शपथ ग्रहण पौने एक बजे होगा। समारोह में निवर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मौजूदगी की कोई सूचना नहीं है। उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

समारोह में कोई केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं होगा : दोनों ही जगह शपथ ग्रहण समारोह में फिलहाल किसी भी केंद्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री के आगमन की सूचना नहीं है। पीएमओ में राज्यमंत्री व जम्मू संभाग के डोडा-कठुआ संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह भी किसी समारोह में शामिल नहीं होंगे। वह 31 अक्टूबर को दिल्ली में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टेचू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एक समारोह में भाग लेंगे, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरि झंडी दिखाएंगे।

नरूला बने माथुर के सलाहकार, खंडारे लद्दाख के पुलिस प्रमुख : केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नौकरशाह और राज्य के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रधान सचिव उमंग नरूला को केंद्र शासित लद्दाख के पहले उपराज्यपाल आरके माथुर का सलाहकार नियुक्त किया है। नरूला 1965 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वह जम्मू प्रांत के मंडलायुक्त भी रह चुके हैं। लद्दाख में पुलिस प्रशासन की कमान 1995 बैच के आइपीएस एसएस खंडारे को सौंपी गई है। दोनों अधिकारी 31 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे।

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना क्षेत्र के अस्तित्व से जुड़ा अहम मसला था। ऐसा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर दिया है। हमें कश्मीर केंद्रित सरकारों के भेदभाव से आजादी मिल गई है। अब क्षेत्र में तेज विकास का इतिहास रचा जाएगा।

-जामियांग सेरिंग नामग्याल
सांसद, भाजपा

जम्मू-कश्मीर गुरुवार से नया केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इसके मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर में बाजार में तैनात सुरक्षाकर्मी। प्रेट्र

इसलिए चुना गया 31 अक्टूबर का दिन

6 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर दो अलग-अलग केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर व लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएगा। केंद्र सरकार ने देश के पहले गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को 31 अक्टूबर को प्रभावी बनाने का फैसला किया है। पटेल ने भारत-पाक विभाजन के बाद विभिन्न रियासतों के भारत में विलय में अहम भूमिका निभाई थी।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था नारा : भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश, एक विधान और एक निशान का नारा दिया था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी।

महिलाओं का बढ़ेगा विश्वास

अनुच्छेद 370 व 35 ए के खत्म होने तथा जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से महिलाओं में भी विश्वास जगा है। पहले जो महिला दूसरे राज्य में शादी करती थी तो शादी के बाद उसके यहां के सभी अधिकार समाप्त हो जाते थे। अब यहां की महिलाएं पूरी तरह से अपने आपको सुरक्षित मान रही हैं और उन्हें काफी खुशी भी है। तीन तलाक का डर भी अब समाप्त हो जाएगा क्योंकि जो पूरे देश में तीन तलाक का कानून बना है अब वह जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा।

विशेष पेज-5

सरोकार

इस सरकारी स्कूल की सभी छात्राएं 'भारतीय'

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित शासकीय आदर्श कन्या आवासीय

संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्राओं का एक ही सरनेम होता है- 'भारतीय'। देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को ये बालिकाएं निराले तरीके से परिभाषित कर रही हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

कड़ा हुआ कानून तो झारखंड में धर्म नहीं बदल रहे लोग

रांची : झारखंड सरकार द्वारा फरवरी में धर्मांतरण कानून (झारखंड धर्म स्वतंत्र

विधेयक 2017) लागू कर देने के बाद राज्य में धर्मांतरण अप्रत्याशित रूप से थम गया है। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, कोडरमा सहित अन्य प्रमुख जिलों में की गई पड़ताल पर आधारित रिपोर्ट। (पेज-10)

अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मसला

यूरोपीय संघ के सांसदों ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार की हवा निकाली

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर के जमीनी हालात का जायजा लेने आए यूरोपीय संघ (ईयू) के सांसदों ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार की हवा निकाल दी। सांसदों ने साफ कहा, अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है। हमारा भारत की अंदरूनी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कश्मीर को दूसरा सीरिया व अफगानिस्तान न बनने देने की संकल्पबद्धता दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरा साथ दिया जाएगा। हमने पाया कि यहां (कश्मीर) आतंकी हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका है।

ज्ञात हो, ईयू सांसदों का 23 सदस्यीय दल दो दिनी दौरे पर गत मंगलवार को श्रीनगर पहुंचा था। बुधवार को मीडिया से बातचीत में इन सांसदों ने न सिर्फ कश्मीर के हालात पर बेबाक राय रखी बल्कि अपने ऊपर लगे आरोपों को भी नकारा। पाक के संबंध में कहा, वहां ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति ठीक नहीं है। उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। कश्मीर में आम लोगों के साथ बातचीत में पाया कि यहां भी आतंकी हिंसा में पाक की भूमिका है। अधिकारियों और विभिन्न संगठनों से चर्चा के दौरान भी कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकियों की फंडिंग में पाकिस्तान का हाथ होने के कई सुबूत दिखाए गए।

श्रीनगर में बुधवार को ईयू के सांसद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए। (वीडियो ग्रैब)। प्रेट्र

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ : यूरोपीय संघ में फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाले हेनरी ने कहा, अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मसला है। इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा और चिंता का विषय आतंकवाद है। भारत इससे लड़ रहा है और इस लड़ाई में हम उसके साथ हैं। हम कुलगाम में पांच श्रमिकों की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। हम लोगों ने यहां सेना, पुलिस और कश्मीर की युवा पीढ़ी से बातचीत करते हुए शांति बहाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

यहां के लोग शांति और विकास चाहते हैं : ब्रिटेन से संबंधित न्यूटन डन ने कहा, यहां लोग आतंकवाद से पूरी तरह तंग हैं। वह शांति और विकास चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। हम भारत को दुनिया का सबसे शांत राष्ट्र देखना चाहते हैं और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम उसके साथ हैं। हमने यहां जो देखा और महसूस किया है, दुनिया में जहां भी मौका मिलेगा, उस पर बात करेंगे।

भारत सरकार सही दिशा में काम कर रही : जर्मनी के लार्स पेट्रिक बर्ग ने कहा, यह यूरोपीय संघ का आधिकारिक दौरा नहीं है। हम चाहते थे कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसकी सच्चाई को जाना जाए। यहां हालात सामान्य बनाने के लिए भारत सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हम यहां कश्मीरियों के मित्र बनकर आए हैं।

कश्मीर में आतंकवाद नहीं चाहते : फ्रांस के थेरी मैरानी ने सीरिया में अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि मैने देखा है कि किस तरह आतंकवाद किसी राज्य, क्षेत्र और समाज को बरबाद करता है। पिछले माह मैं सीरिया में ही था, वहां आतंकवाद से हुई तबाही को देखा है। हम नहीं चाहते कि कश्मीर का भी यही हाल हो। कश्मीर को दूसरा सीरिया और अफगानिस्तान नहीं बनने दे सकते।

यह भी बोले

- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरा साथ देंगे यूरोपीय देश
- कश्मीर को दूसरा सीरिया व अफगानिस्तान कतई नहीं बनने देंगे
- कश्मीर में आतंकी हिंसा में पड़ोसी मुल्क की भूमिका, दहशतगर्दों को वित्त मुहैया कराने में भी पाकिस्तान का हाथ

दौरे को लेकर विवाद अनावश्यक पेज>>6

अयोध्या का मामला दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक : जस्टिस बोबडे

नई दिल्ली, जेएनएन

भारत के नामित मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि अयोध्या का मामला दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। सोशल मीडिया पर जजों के कामकाज की आलोचना पर अफसोस जताते हुए कहा, अधिकांश जज जिनकी चमड़ी मोटी नहीं है, वह इससे क्षुब्ध हो जाते हैं। फैसले की आलोचना के बजाय जज की आलोचना से मानहानि का मामला बनता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट सुस्त पड़ चुके संवैधानिक मामलों से निपटने के लिए पांच जजों की स्थायी संवैधानिक पीठ बना सकती है।

18 नवंबर को 47वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जस्टिस बोबडे ने बुधवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि अयोध्या मामला निश्चित रूप से अहम है। बोबडे भी इस मामले की संविधान पीठ का हिस्सा हैं। इस मामले में फैसला 17 नवंबर से पहले आना है। चूंकि इसी दिन मौजूदा सीजेआइ रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस बोबडे 17 महीनों के लिए सीजेआइ के पद पर रहेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति 23 अप्रैल, 2021 को होनी है।

शरद अरविंद बोबडे फाइल

नामित सीजेआइ ने जजों के कामकाज की आलोचना पर अफसोस जताया

63 वर्षीय बोबडे ने कोलेजियम में उच्च न्यायालयों के लिए जजों के चयन की मंत्रणा को सार्वजनिक नहीं करने का पक्ष लेते हुए कहा, यह कोई बात गुप्त रखने का मामला नहीं है, बल्कि निजता के लिहाज से निजी रखने का विषय है। किसी की नकारात्मक बातें बेवजह सबके सामने क्यों लाई जाएं। जनता की कुछ जानने की इच्छा को पूरा करने के लिए लोगों की साख को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। कोलेजियम में विचार किए गए उन नामों को सामने लाया जा सकता है, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन वह नाम नहीं जिन्हें खारिज किया गया। उन्हें रिजेक्ट करने के कारण भी सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। ज्ञात हो, 2017 में तत्कालीन सीजेआइ दीपक मिश्रा ने कोलेजियम की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डालने का निर्णय लिया था।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

भारत-सऊदी अरब के बीच सुरक्षा संबंधों की नई शुरुआत

नई दिल्ली : सऊदी अरब और भारत के बीच सुरक्षा संबंधों की नई शुरुआत हुई है। बढ़ते सुरक्षा सहयोग की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत-ऊदी अरब के बीच हुए 12 समझौतों में से तीन सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

सोने के रूप में रखा कालाधन वैध बनाने का मौका देगी सरकार

नई दिल्ली : सोने के रूप में रखे कालेधन को रिकवर करने के लिए सरकार गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी में है। नई योजना के तहत अघोषित सोने की जानकारी और उस पर टैक्स देकर इसे वैध सोने में बदला जा सकेगा।

राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले से पहले संघ परिवार में मंथन तेज

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

▶ दिल्ली में तीन दिवसीय विशेष बैठक शुरू, भागवत और अमित शाह हुए शामिल

सुप्रीम कोर्ट से अगले माह राम मंदिर पर फैसला आने से पहले संघ परिवार में मंथन तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में तीन दिनी विशेष बैठक बुधवार को शुरू हुई। इस बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ट्वीट कर कहा है कि श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी आए उसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, यह सबका दायित्व है।

दिल्ली के छतरपुर के ध्यान साधना केंद्र में बैठक के पहले दिन बुधवार को आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। सर संघचालक मोहन भागवत व सरकार्यवाह भैय्या जी जोशी की विशेष मौजूदगी के अलावा सभी सह सरकार्यवाह और क्षेत्रीय प्रचारकों को भी विशेष रूप से बुलाया गया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। पहले यह बैठक 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हरिद्वार में होनी थी, जो किन्हीं कारणों से निरस्त हो गई।

संघ के एक पदाधिकारी ने कहा, अयोध्या पर कोर्ट के फैसले को लेकर यह आपात बैठक हो रही है। इसमें सभी संभावित फैसलों के साथ उसके विकल्पों पर भी विचार-विमर्श हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, संघ फैसला पक्ष में आने को लेकर आश्वस्त है। कोई पेच फंसने की स्थिति में आगे की रणनीति क्या हो सकती है? किस तरह राम भक्तों को संतुष्ट किया जा सकता है? इन सब सवालों का हल तलाशा जा रहा है।

जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार : फड़नवीस

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- फिर चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता, मोदी-शाह के साथ उद्धव का भी जताया आभार
- कई भाजपा नेताओं ने माना, शिवसेना के साथ जारी है सरकार बनाने की अनौपचारिक बातचीत

सहयोगी दल शिवसेना के तमाम नखरों और 'विकल्प खुले रहने' की धमकियों के बीच पुनः भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फड़नवीस ने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में 'महागठबंधन' की सरकार बनेगी और पूरे पांच साल चलेगी। फड़नवीस के विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही भाजपा ने शिवसेना के साथ अनौपचारिक वार्ता का दौर तेज कर दिया है। कई भाजपा नेताओं ने स्वीकार किया कि शिवसेना से सरकार बनाने की अनौपचारिक बातचीत जारी है।

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फड़नवीस ने अब तक मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ-साथ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का भी आभार व्यक्त किया। फड़नवीस ने कहा, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने जनादेश महागठबंधन के पक्ष में दिया है इसलिए बहुत जल्द महागठबंधन राज्य में सरकार बनाने जा रहा है। शिवसेना द्वारा 'विकल्प खुले रहने' की बात पर उन्होंने कहा, 'वैकल्पिक सरकार' की भी अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन यह मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं है। फड़नवीस के अनुसार, 1995 के बाद से किसी भी दल को 75 से ज्यादा सीटें नहीं मिली थीं, लेकिन भाजपा को पिछले चुनाव में 122 और इस बार 105 सीटें मिली हैं। माना जा रहा है कि भाजपा शिवसेना को उपमुख्यमंत्री पद के साथ उसके संख्या बल के अनुसार, पिछली सरकार के बराबर मंत्री पद देने पर राजी हो जाएगी। गृह, नगर विकास, राजस्व और सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय पर शिवसेना के साथ कोई समझौता होने की गुंजाइश कम है।

मुंबई में बुधवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडनवीस (मध्य में) को बधाई देते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर (दाएं से दूसरे)। साथ में मौजूद महासचिव भूपेंद्र यादव (दाएं) भाजपा की राज्य प्रभारी सरोज पांडे (बाएं)। प्रेट्र

इससे पहले भाजपा ने पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पूर्ण की। सभी विधायक सिर पर भगवा साफा बांधकर विधान भवन में आयोजित बैठक में पहुंचे। वे 'जय शिवाजी' और 'भारत माता की जय' के नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर व अविनाश राय खन्ना भी उपस्थित थे।

शिवसेना विधायक आज चुनेंगे नेता : शिवसेना के विधायक गुरुवार को मध्य मुंबई स्थित सेना भवन में अपना नेता चुनेंगे। इस बीच, दो निर्दलीय विधायकों मंजुला गावित और चंद्रकांत निंबा पाटिल ने उद्धव ठाकरे से भेंट के बाद शिवसेना को समर्थन की घोषणा की। छह निर्दलीय विधायक पहले ही भाजपा को समर्थन दे चुके हैं। ये भाजपा के ही बागी नेता हैं।

संजय राउत बोले, शिवसेना का भाजपा गठबंधन में रहना जरूरी पेज>>4

हाल-बेहाल

गाजियाबाद लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, 14 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में आठ शहर उत्तर प्रदेश के रहे, दिल्ली एनसीआर में धुंध के साथ ही वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा

उत्तर भारत में और जहरीली हुई हवा

जेएनएन, नई दिल्ली

दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में हवा और जहरीली हो गई है। बुधवार को भी दिन में वायु प्रदूषण के चलते दृश्यता कम रही। दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा में भी खासा इजाफा देखने को मिला। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 400 के अंक पर था। बुधवार को इसमें 19 बिंदुओं का इजाफा हुआ और यह 419 हो गया। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। शाम चार बजे हवा में पीएम 10 की मात्रा 451 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 2.5 की मात्रा 273 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। मानकों के अनुसार, हवा में पीएम 10 की मात्रा 100 और पीएम 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण हरियाणा और पंजाब में जलाई गई पराली को बताया जा रहा है।

गाजियाबाद लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। देश के 14 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में आठ शहर उत्तर प्रदेश के रहे। लखनऊ की हवा में भी प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। लखनऊ में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स बढ़कर 326 के स्तर में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार गाजियाबाद लगातार दूसरे दिन भी देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। यहां एक्यूआइ 478 के स्तर में दर्ज किया गया। बागपत 461 और नोएडा में 450 रिकार्ड हुआ। उधर, हरियाणा स्थित पानीपत अचानक प्रदूषण के स्तर में चार सौ का आंकड़ा पार करते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया। देश के 12 शहर एक्यूआइ में 400 से आगे रहे।

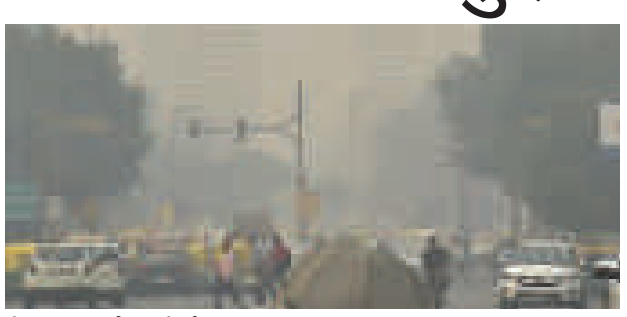

धुंध में दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में धुंध और धुएं की मोटी परत छाई हुई है। यह दृश्य बाराखंबा रोड पर बुधवार को दोपहर 1.10 बजे का है। संजय

अरब सागर के ऊपर बने सुपर साइक्लोन का है असर : मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि अरब सागर के ऊपर बने सुपर साइक्लोन का असर उत्तराखंड सहित पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छायी धुंध के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार दीपावली के दिन से समूचे उत्तर भारत में जो धुंध छायी हुई है उसके अन्य कारकों में पटाखों से फैले प्रदूषण भी है। उत्तराखंड में एक माह से बारिश नहीं होने से भी धूल के कणों के अधिक ऊंचाई तक पहुंचने से धुंध अधिक दिखाई दे रही है।

शहरों का एयर इंडेक्स

शहर	एयर इंडेक्स
फरीदाबाद	404
गाजियाबाद	478
नोएडा	450
ग्रेटर नोएडा	438
गुरुग्राम	365

इंडेक्स का स्तर और श्रेणी

0 से 50	अच्छा
50 से 100	संतोषप्रद
100 से 200	सामान्य
200 से 300	खराब
300 से 400	बहुत खराब
400 से ऊपर	गंभीर / आपातकालीन

फिर रद हुई पिथौरागढ़ की फ्लाइट

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ की फ्लाइट बुधवार को फिर रद कर दी गई। पिथौरागढ़ में बेहद कम दृश्यता के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया। मंगलवार को भी हिंडन से पिथौरागढ़ के लिए उड़े विमान को देहरादून में लैंड कराया गया था।

गो तस्करी मामला : पहलू खान समेत चार के खिलाफ दर्ज केस होगा रद

जागरण संवाददाता, जयपुर

- राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए आदेश, कहा- मामला साबित नहीं हुआ
- पहलू के दोनों बेटों और ट्रक चालक की ओर से दायर की गई थी याचिका

देश के चर्चित पहलू खान गो तस्करी मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्मादी हिंसा (मॉब लिंचिंग) में मारे गए पहलू खान, उसके दोनों बेटों इरशाद और आरिफ के साथ ही ट्रक चालक खान मोहम्मद के खिलाफ पुलिस में दर्ज एफआइआर रद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस चारों के खिलाफ गो तस्करी का मामला साबित नहीं कर सकी है।

पहलू खान, उसके दोनों बेटों और खान मोहम्मद के खिलाफ पुलिस ने गो तस्करी को लेकर अप्रैल 2017 में एफआइआर दर्ज की थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी ने एफआइआर रद करने के आदेश दिए। एफआइआर रद करने को लेकर इरशाद, आरिफ और खान मोहम्मद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि पहलू खान, उसके दोनों बेटों और ट्रक चालक के पास से बरामद की गई गायें दुधारू थीं। इन गायों के साथ दो बछड़े भी थे। पहलू खान के पास जयपुर के पशु हटवाड़ा से गाय खरीदने की रसीद (रवन्ना) भी थी। इन गायों को हरियाणा के नूंह स्थित डेयरी में ले जाने के प्रमाण भी मिले हैं।

पुलिस चारों पर गो तस्करी का मामला साबित नहीं कर सकी है। पहलू खान की मौत होने के कारण उसके खिलाफ तो मामला स्वतःही समाप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था।

क्या है मामला पेज>>7